आज़ादी का
अमृत महोत्सव

साप्ताहिक सूचना पत्र

(दिनांक 09.01.2023 से 14.01.2023)

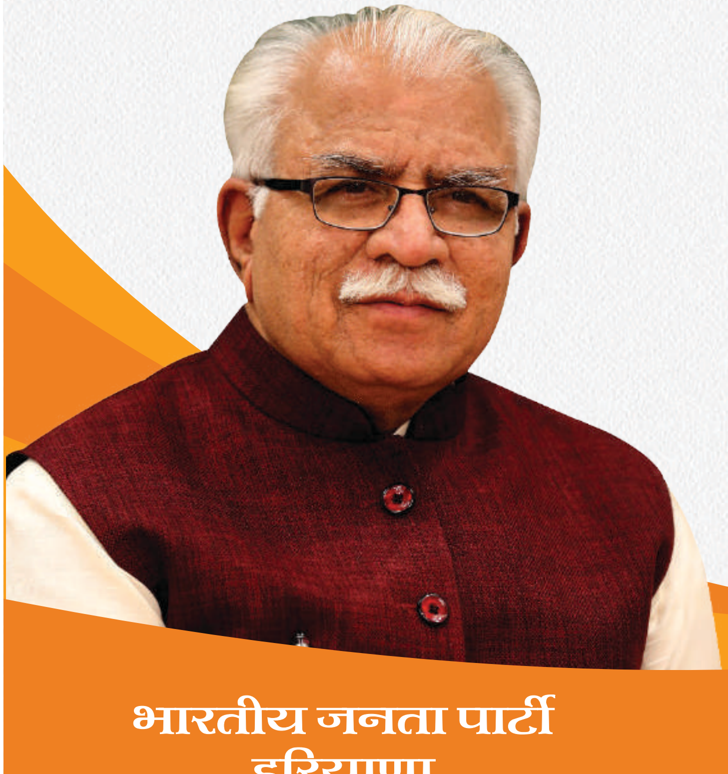

भारतीय जनता पार्टी
हरियाणा

साप्ताहिक सूचना पत्र

‘पीपीपी’ डाटा को अपडेट करने के संबंध में अहम बैठक

(दिनांक 09.01.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने अतिरिक्त जिला उपायुक्तों के साथ बैठक कर सभी को निर्देश दिए कि परिवार पहचान पत्र में दर्ज परिवारों के विवरणों को अपडेट करने के लिए जिला, खण्ड व गांव स्तर पर विशेष कैंप लगाए जाएं।

इसके अलावा, अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालयों व ई–दिशा केंद्रों में भी विशेष काउंटर की व्यवस्था की जाएगी, जहां पर नागरिक सरलता से पीपीपी डाटा को अपडेट करवा सकेंगे।

अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि पीपीपी में डाटा के अपडेशन के कार्य में तेजी लाई जाए और इस कार्य को 25 जनवरी तक अवश्य पूरा किया जाए, ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। पीपीपी में जन्म तिथि, आय, शैक्षणिक योग्यता, व्यवसाय सहित 21 विभिन्न कॉलम अपडेट किये जा रहे हैं।

साप्ताहिक सूचना पत्र

यदि किसी परिवार का राशन कार्ड पीपीपी मे डाटा अपडेशन के दौरान कट गया है, तो ऐसे नागरिक 18001802087 और 1967 या 01723968400 टोल फ्री नंबरों पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, उनकी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि इन टोल फ्री नंबरों का अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार करें।

पीपीपी डाटा के अपडेशन के दूरुस्त होने तक पुरानी पद्धति अनुसार राशन दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में लगभग 7 हजार पीडीएस की दुकानों पर 2 क्विंटल अनाज का अतिरिक्त प्रबंध करने के निर्देश दिए।

पीपीपी के माध्यम से ऑटोमेटिक राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया चल रही है। 1. 80 लाख वार्षिक आय के मानदंड अनुसार 12 लाख नये परिवार बीपीएल सूची में शामिल हुए हैं।

प्रेसवार्ता का आयोजन

(दिनांक 09.01.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते करते हुए कहा कि ग्रुप सी के लगभग 40 हजार पदों पर जल्द भर्ती की जायेगी।

ग्रुप सी के पदों की भर्ती के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा हो चुकी है, जिसका परिणाम शीघ्र ही घोषित होने वाला है। परिणाम आने के बाद ग्रुप सी के लगभग 40 हजार पदों को विज्ञापित किया जाएगा। इसके अलावा, ग्रुप–डी के पदों की भर्ती के लिए भी जल्द सीईटी परीक्षा आयोजित की जाएगी और लगभग 17 से 20 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। सीईटी परीक्षा की वैधता 3 साल है। हालांकि, सीईटी परीक्षा का आयोजन हर वर्ष किया जाएगा, जो भी उम्मीदवार अपने नंबर में सुधार करना चाहता है, वह भी दोबारा परीक्षा दे सकते हैं।

उन्होंने कहा कि सी.एम.आई. द्वारा

साप्ताहिक सूचना पत्र

प्रदर्शित बेरोजगारी कें आंकड़े पूर्णतः आधारहीन हैं। सी.एम.आई. का आंकड़ा कुछ लोगों के सैंपल सर्वे पर आधारित होता है। पूर्व में इसी एजेंसी ने हरियाणा की बेरोजगारी दर को 2 प्रतिशत दिखाया था।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 12 लाख नये परिवारों का नाम भी अभी बीपीएल सूची में शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पीपीपी के माध्यम से ऑटोमेटिक राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया चल रही है। बीपीएल आय के नये मानदंड के अनुसार 12 लाख नये परिवारों का नाम बीपीएल सूची में जुड़ा है। उन्होंने कहा कि गलत ढंग से किसी का राशन कार्ड नहीं काटा गया है। हमारी मंशा गलत नहीं है, लेकिन गरीब को उसका हक मिले, यही हमारा उद्देश्य है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 1.32 लाख परिवार ऐसे हैं, जो इनकम टैक्स रिर्टन भरते हैं। 51,489 सरकारी व अनुबंधित कर्मचारी हैं। इसी प्रकार, 2119

सरकारी पेंशनधारक हैं। 1.80 लाख रुपये से अधिक आय वाले 3,44,821 परिवार हैं, जिनके नाम बीपीएल सूची से बाहर हुए हैं। इसके अलावा, 2 लाख औद्योगिक श्रमिक तथा 4 लाख रुपये से अधिक फसल बिक्री करने वाले 7,416 किसानों का भी डाटा हमारे पास आया है। इन दोनों श्रेणियों का दोबारा सर्वे किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन परिवारों का सालाना 9 हजार रुपये से अधिक बिजली बिल आता है, ऐसे 2,27,000 परिवारों का नाम भी बीपीएल सूची से बाहर हुआ है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

अतिरिक्त उपायुक्तों को इस संबंध में निर्देश जारी किये गए हैं कि राशन कार्ड से संबंधित हर प्रकार की शिकायत का 15 दिन में समाधान किया जाए। यदि निर्धारित समय में उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता, तो उन्हें इस माह का राशन मिलेगा।

जिनका नाम बीपीएल सूची से बाहर हुआ है, ऐसे नागरिक 18001802087 और 1967 टोल फ्री नंबरों पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, उनकी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि अंत्योदय परिवारों के लिए चिरायु हरियाणा योजना भी चलाई गई है। ऐसे लगभग 29 लाख परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये तक के मुफ्त ईलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है।

पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर उन्हें और अधिक स्वायत्ता प्रदान करने की घोषणा करते हुए कहा कि अब से पंचायती राज संस्थाओं की अपनी आय में से होने वाले 2 लाख रुपये तक के विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति चुने हुए जन प्रतिनिधियों द्वारा उनके स्तर पर ही दी जाएगी। सरपंच, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के चेयरमैन द्वारा यह स्वीकृति प्रदान की जाएगी। 2 लाख रुपये तक के कार्यों की तकनीकि स्वीकृति जूनियर इंजीनियर देगा और इन कार्यों के लिए किसी प्रकार का कोई टेंडर नहीं होगा।

मुख्यमंत्री जी इस बारे और अधिक जानकारी देते हुए कहा कि 2 लाख से 25 लाख रुपये तक के कार्यों की तकनीकि स्वीकृति एसडीओ देगा। इन कार्यों के लिए हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के माध्यम से अल्पावधि के टेंडर किये जाएंगे। 25 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के कार्यों की तकनीकि स्वीकृति एक्सईएन देगा। एक करोड़ से 2.5 करोड़ रुपये तक के कार्यों की तकनीकि स्वीकृति अधीक्षक अभियंता तथा 2.5 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य की तकनीकी स्वीकृति चीफ इंजीनियर देगा।

साप्ताहिक सूचना पत्र

उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों की फिक्स्ड डिपोजिट भी होती है। गांवों में विकास कार्यों के लिए यदि धन की आवश्यकता होती है तो इस डिपोजिट में से एक साल में 50 लाख रुपये तक या कुल डिपोजिट की 10 प्रतिशत राशि, जो भी अधिक हो, जिला उपायुक्त रिलीज कर सकता है। इससे अधिक राशि के लिए जिला उपायुक्त इस विषय को राज्य सरकार को भेजेंगे।

उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए यदि राशि कम पड़ती है और पंचायती राज संस्थाओं की मांग पर राज्य सरकार अतिरिक्त बजट प्रदान करती है, तो 25 लाख रुपये से कम काम के लिए राशि सीधे उन्हें दे दी जाएगी। 25 लाख रुपये से ज्यादा के काम ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किये जाएंगे। इसके लिए 25 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक की प्रशासनिक स्वीकृति विभाग के निदेशक द्वारा दी जाएगी और इस कार्य की तकनीकि स्वीकृति एक्सईएन देगा। एक करोड़ से 2.5 करोड़ रुपये तक प्रशासनिक स्वीकृति प्रशासनिक सचिव तथा तकनीकि स्वीकृति अधीक्षक अभियंता देगा। 2.5 से 10 करोड़ रुपये तक के कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति संबंधित मंत्री तथा तकनीकि स्वीकृति चीफ इंजीनियर देगा। दस करोड़ रुपये से अधिक के कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति मुख्यमंत्री स्तर पर होगी तथा तकनीकि स्वीकृति चीफ इंजीनियर द्वारा दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि पहले कार्य करवाने के लिए तकनीकी स्वीकृतियों में ही बहुत लंबा समय लगता था, लेकिन अब उनके स्तर पर स्वीकृतियां होने से यह कार्य जल्दी होंगे और कार्यों में पारदर्शिता भी आएगी।

साप्ताहिक सूचना पत्र

भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

(दिनांक 11.01.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री ने अपने आवास संत कबीर कुटीर पर भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की।

बैठक में मुख्यमंत्री जी ने प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, शामलात देह व जुमला मुश्तरका मालकान व आबाद कार, पट्टेदार, ढोलीदार, बुटमीदार व मुकरीरदार व अन्य काश्तकारों को मालिकाना हक देने के मामले का स्थायी हल निकाला जाएगा। इस विषय में प्रदेश सरकार नया कानून बना रही है। प्रतिनिधियों ने बैठक में अपनी कई मांगें रखी, जिन पर सहमति बन गई और इसके लिए प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

पुराने कानूनों का अध्ययन करने व नये कानून तैयार करने के लिए विशेष कमेटी गठित की हुई है, जिसमें वे स्वयं तथा उप मुख्यमंत्री, विकास एवं पंचायत मंत्री, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री तथा महाअधिवक्ता शामिल हैं। इस कमेटी

की 2 बैठकें हो चुकी हैं और अधिकारियों को कानून का प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। यह कार्य अंतिम चरण में है, जल्द ही इससे संबंधित विधेयक विधान सभा में लेकर आएंगे। किसान यूनियन के वकील भी कमेटी को कानून बनाने से संबंधित यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो वे भी दे सकते हैं। इस पर किसान यूनियन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि जो किसान वर्षों से ऐसी जमीनों पर मकान बना कर रह रहे हैं या खेती कर रहे हैं, उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। उनसे जमीन नहीं छुड़वाई जाएगी। लेकिन सरकार ने सख्ती की है ताकि इस प्रकार का कोई नया कब्जा न हो सके।

प्रदेश में पानी की उपलब्धता लगातार कम होती जा रही है, इसको देखते हुए वर्तमान में उपलब्ध पानी का उपयुक्त प्रबंधन करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार द्वारा भू–जल रिचार्जिंग के लिए बोरवैल भी लगाए जा रहे हैं।

किसान यूनियन के प्रतिनिधियों के सुझाव को मानते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही एक नई योजना लेकर आएंगे, जिसके तहत भू–जल रिचार्जिंग के लिए किसान अपने खेत में बोरवेल लगा सकेंगे और राज्य सरकार इस पर सब्सिडी देने का प्रावधान बनाएगी।

इसके लिए जल्द ही योजना का खाका

साप्ताहिक सूचना पत्र

तैयार किया जाएगा। 3 साल तक उस बोरवेल का रखरखाव भी किसान ही करेंगे। इस कदम के लिए किसान यूनियन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गन्ने के मूल्य को लेकर सरकार ने कृषि मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, जो गन्ने की लागत, चीनी का रेट, उसकी रिकवरी सहित अन्य संबंधित विषयों का अध्ययन कर रही है और जल्द ही सरकार को रिपोर्ट देगी।

राज्य सरकार चीनी मिलों की क्षमता भी बढ़ा रही है। मिलों में अब एथेनॉल बनाने की दिशा में भी तेजी से कार्य हो रहा है, ताकि मिलों के घाटे में कुछ कमी लाई जा सके।

बैठक में किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों ने हाईवे या एक्सप्रेस–वे के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण के कारण खेतों में जाने के रास्ते की व्यवस्था नहीं होने की समस्या भी रखी। इस पर मुख्यमंत्री जी ने हुए कहा कि राज्य सरकार सड़कों के दोनों तरफ की जमीनों की पुनः चकबंदी करने का प्रबंध कर रही है, ताकि किसी किसान की जमीन यदि सड़क के दोनों तरफ आ गई है तो उसे सड़क के एक तरफ जमीन मिल जाए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। चकबंदी करने उपरांत किसानों को 4–5 करम का रास्ता प्रदान करने की व्यवस्था भी की जा सकेगी।

यूनियन के प्रतिनिधियों द्वारा भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन की मांग पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में सरकारी परियोजनाओं के लिए एक ईंच भूमि का भी अधिग्रहण नहीं किया गया है। हमारी सरकार ने ई–भूमि पोर्टल शुरू किया हुआ है, जिसके माध्यम से परियोजनाओं के लिए भूमि मालिकों की सहमति पर उनके रेट के अनुसार सरकार उनकी जमीन ले रही है। इस प्रकार भू–मालिकों की आपसी सहमति से अब तक लगभग 800–900 एकड़ भूमि सरकार खरीद चुकी है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

चिरायु योजना की समीक्षा बैठक

(दिनांक 11.01.2023)

प्रभाव : चिरायु योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना का प्रदेश सरकार ने दायरा बढ़ाकर चिरायु हरियाणा योजना लागू की है। इसलिए अधिकारी चिरायु योजना के पंजीकरण के कार्य को प्राथमिकता दें ताकि जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्तियों को समय पर इसका लाभ मिल सके।

केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। हरियाणा में 15,51,798 परिवार इस योजना में कवर हो रहे थे। इनमें से लगभग 9 लाख परिवार इस योजना का लाभ उठा रहे थे। चिरायु योजना लागू करने से प्रदेश में अब लगभग 20 लाख परिवार और इस योजना में जुड़ गए हैं।

सरकार ने इस योजना का लाभ अधिक परिवारों को देने के लिए बीपीएल की आय सीमा को बढाकर 1.80 लाख रुपए कर दिया। अब इस योजना के तहत लगभग 29 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

इसको लेकर आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेजी से की जा रही है। जिन

परिवारों के कार्ड नहीं बने हैं उनके कार्ड बनाये जा रहे हैं। इसके लिए स्वास्थ्य केन्द्रों पर अतिरिक्त कांउटर बनाये गए हैं।

चिरायु योजना के तहत 44 लाख से ज्यादा नये गोल्डन कार्ड बने। चिरायु योजना शुरू करने से पहले आयुष्मान भारत योजना में प्रदेश के 28,89,287 व्यक्तियों के गोल्डन कार्ड बनाए गए थे। चिरायु योजना के तहत अब 44,15,771 और व्यक्तियों के नये गोल्डन कार्ड बन चुके हैं। इन्हें मिलाकर गोल्डन कार्ड पाने वालों की संख्या बढ़कर 73 लाख से अधिक हो गई है। इस माह के अंत तक सब लाभर्थियों के गोल्डन कार्ड बना दिए जाएंगे।

चिरायु योजना के तहत प्रदेश में कुल 715 अस्पताल, जिनमें 539 निजी अस्पताल और 176 सरकारी अस्पताल शामिल हैं। मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारीयों को निर्देश दिए की हर एक पात्र व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए और कोई भी गरीब व्यक्ति इलाज के लिए परेशान नहीं होना चाहिए।

कौशल विकास विभाग के साथ बैठक

(दिनांक 11.01.2023)

प्रभाव : हरियाणा के 10 जिलों में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की तर्ज पर इनोवेटिव स्किल स्कूल खोले जाएंगे। स्किल एजुकेशन के केजी टू पीजी मॉडल और नई शिक्षा नीति के लक्ष्यों के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। इन स्कूलों को श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय संचालित करेगा। सभी जिलों में स्कूल स्तर पर स्किल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने केजी से पीजी तक स्किल एजुकेशन के मॉडल को लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके माध्यम से नई शिक्षा नीति के अनुसार केजी से पीजी तक स्किल एजुकेशन के लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकेगी।

स्कूल स्तर पर स्किल एजुकेशन शुरू किए जाने से कई लक्ष्य एक साथ पूरे होंगे। इससे न केवल ड्रॉपआउट कम होगा, बल्कि ग्रॉस एजुकेशन रेशो (जीईआर) को भी बढ़ाया जा सकेगा। साथ ही साथ उद्योग को कुशल मानवीय संसाधन मिलेंगे, जो गुणवत्ता और उत्पाद को बढ़ाने में सहायक साबित होंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। यह अभिनव प्रयोग हरियाणा की स्कूल एजुकेशन में मील का पत्थर साबित होगा।

स्किल इनोवेटिव स्कूल खुलने के बाद रोजगार के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। इसके माध्यम से विद्यार्थी स्कूल एजुकेशन के दौरान ही कौशल की तरफ आकर्षित होंगे और उच्चतर शिक्षा में भी वोकेशनल तथा स्किल एजुकेशन के प्रति रुझान बढ़ेगा। स्किल सेट में आईटी, ऑटोमोटिव, एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्यूटी वेलनेस, डिजाइन मेकिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, हैंडीक्राफ्ट्स, मास मिडिया, हेल्थ केयर, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर, फूड प्रोडक्शन व सिक्योरिटी जैसे विषय शामिल हैं।

साप्ताहिक सूचना पत्र

सरपंच, पंचायत समिति व जिला परिषद् सदस्यों के साथ संवाद

(दिनांक 12.01.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने पलवल और फरीदाबाद जिला के सरपंचों, पंचायत समिति व जिला परिषद् सदस्यों के साथ मंत्रणा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अच्छा काम करके दिखाओ और जनता से वाहवाही पाओ।

उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचे प्रतिनिधियों को भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी एवं अंत्योदय आधारित व्यवस्था स्थापित करने का संकल्प भी दिलवाया।

उन्होंने कहा कि पंचायतों की परंपरा ऋग्वेद के समय से चली आ रही है और पंच को परमेश्वर का दर्जा मिला है। ऐसे में नए दायित्व का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करते हुए पुराने समय से पंचायतों पर भरोसे को कायम रखना। उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वामी

विवेकानंद की जयंती, राष्ट्रीय युवा दिवस, लोहड़ी, मकर संक्रांति व पोंगल की शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान सरकार ने हरियाणा में आज अपने कार्यकाल के तीन हजार दिन भी पूरे कर लिए है। आजादी से पहले महात्मा गांधी ने ग्राम–स्वराज का स्वप्न देखा था कि किस प्रकार ग्रामीण भारत की शासन व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए ताकि आजादी का संदेश गांव–गांव तक पहुंच सके। पुराने समय से कायम खाप–पंचायतों ने समय–समय पर सराहनीय कार्य किए हैं। बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाने में भी पंचायतों की प्रशंसनीय भूमिका रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के सर्वसम्मति से चुने गए प्रतिनिधियों के लिए राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है। उन्होंने कहा कि इस बार 70 हजार प्रतिनिधियों में से 40 हजार प्रतिनिधि सर्वसम्मति से चुने गए हैं। इससे

साप्ताहिक सूचना पत्र

सामाजिक सौहार्द व आपसी भाईचारे को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने पंचायतों को स्वायत्त बनाने की दिशा में अनेक कार्य किए हैं। पढ़ी–लिखी पंचायतों के साथ–साथ सरकार ने इस बार महिलाओं को 50 प्रतिशत पंचायतों में प्रतिनिधित्व दिया है, जिसके चलते इस बार बड़ी संख्या में बेटियां भी पंचायतों में प्रतिनिधि चुनी गई हैं।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि अब पंचायतों को स्वायत्त बनाने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद अपना बजट खुद तय करते हुए अपने क्षेत्र के विकास में धनराशि का स्वयं उपयोग कर सकेंगी। इस कार्य में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। इस नीति को प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा सरकार ने 1100 करोड़ रुपये पंचायती राज संस्थाओं के खातों में हस्तांतरित भी कर दिए हैं। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को प्रतिवर्ष अपना बजट निर्धारित करने के लिए भी कहा।

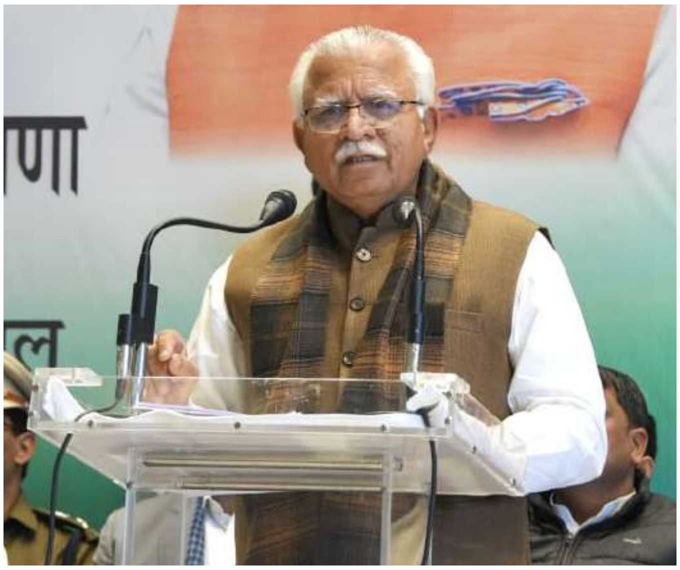

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार भी अच्छा कार्य करने वाली पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही जो गलत कार्य करेंगे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ते हुए दंडित भी किया जाएगा। इसके साथ ही गांव में विकास के लिए सोशल ऑडिट कराने व प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी को संरक्षक बनाने का भी प्रयोग किया गया है। ऑडिट टीम का चयन ग्राम सभा तय करेगी। साथ ही संरक्षक अधिकारी ग्राम सभा का आयोजन कराने व आमजन को कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी के लिए सलाह दे सकेंगे।

जी–20 सम्मेलन की बैठकों की तैयारियों के संबंध में बैठक

(दिनांक 12.01.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने जी–20 शिखर सम्मेलन की प्रदेश में होने वाली संभावित बैठकों की तैयारियों के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और किए जाने वाले प्रबंधों की समीक्षा की।

उन्होंने उच्च अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यह हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि प्रदेश को इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है।

जी–20 शिखर सम्मेलन की कुछ बैठकें गुरुग्राम में मार्च में आयोजित होंनी प्रस्तावित हैं और इसकी सफलता के लिए सभी प्रबंध समय पर सुनिश्चित करें ताकि भारत की 'अतिथि देवो भव' के साथ हरियाणा की स्मृद्ध संस्कृति की अमिट छाप और गुरुग्राम–एक ग्लोबल सिटी का संदेश भी सभी जी –20

सदस्य देशों में जाए।

मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जी–20 सदस्य देशों के शिष्टमंडल की सुविधा हेतू लायजन ऑफिसर लगाए जाऐ। साथ ही, संभावित बैठकों के स्थल व उसके आस–पास के क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किये जाएं। इसके अलावा, आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आयोजन स्थल के पास अस्पतालों को भी चिह्नित करें।

मुख्यमंत्री जी ने हैरिटेज एवं पर्यटन विभाग व सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विभिन्न देशों के शिष्टमंडल का हरियाणा में आगमन होगा तो उन्हें राज्य की संस्कृति व विरासत से परिचय करवाने हेतू विशेष प्रबंध किये जाएं। आयोजन स्थल पर हरियाणा थीम कॉर्नर भी स्थापित किया जाए, जहां मेहमानों के लिए हरियाणा के विकास गाथा संबंधित जानकारी उपलब्ध हो और साथ ही सांस्कृतिक विरासत की झलकियां भी उन्हें देखने को मिल सकें।

साप्ताहिक सूचना पत्र

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जी–20 शिखर सम्मेलन के दौरान ही अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला भी आयोजित होने वाला है।

जी–20 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को भी इस मेले में आमंत्रित किया जाएगा। इस मेले के माध्यम से सभी मेहमानों को न केवल हरियाणा बल्कि देश–विदेश के कलाकारों की कलाकृतियां, हथकरघा, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक ताने–बाने की समृद्धि और विविधता देखने को मिलेगी। इस कार्य में गैर–सरकारी संगठनों को भी शामिल किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि यह कार्यक्रम लोगों का कार्यक्रम बनाए। युवाओं, विशेषकर स्कूल, कॉलेजों के विद्यार्थियों को विश्व में जी–20 देशों के महत्व व भूमिका के बारे जानकारी दी जाए। इसके लिए विश्वविद्यालय के छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा छात्र–छात्राओं के लिए निबंध, डिबेट प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन किया जा सकता है।

कार्यक्रमों के दौरान हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक, कला एवं संस्कृति विभाग के निदेशक और अतिरिक्त निदेशक, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग को सम्मिलित कर एक सांस्कृतिक समिति बनाई गई है।

फरीदाबाद जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक

(दिनांक 12.01.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने फरीदाबाद में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कुल 14 शिकायतें रखी गई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निपटान किया गया।

मुख्यमंत्री जी ने बैठक में सैनिक कालोनी फरीदाबाद में गलत ढंग से बिल्डिंग बनाने, रजिस्ट्री व स्टैंप मामले में मिली एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मामले की जांच विजिलेंस को सौंपने के आदेश दिए हैं।

बैठक में जेजे कैंप निवासी सुभाष मिश्रा ने 1993 में सेक्टर–30 एतमादपुर में

साप्ताहिक सूचना पत्र

दिए गए भूखंडों पर कब्जा न मिलने की शिकायत पर एचएसवीपी के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि यहां 388 व्यक्तियों की सूची ऐसी है, जिनकी आईडी दिल्ली की थी। इस मामले की जांच की गई और जांच करने के उपरांत 52 आवेदकों की आईडी दिल्ली की पाई गई। इस पर मुख्यमंत्री ने अगली मीटिंग तक पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को एनएच–2 मथुरा हाईवे पर बदरपुर बार्डर से पलवल, जहां जरूरत होगी वहां फुट ओवरब्रिज बनाने की रिपोर्ट देने तथा आगरा कैनाल कनेक्टिंग ड्रेन के पानी से खराब हुई बादशाहपुर गांव के किसान रामलाल हंस की फसलों की गिरदावरी करावाकर नियमानुसार मुआवजा देने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने बैठक उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 8 साल के कार्यकाल में फरीदाबाद जिला विकास में आगे बढ़ा है। फरीदाबाद का विस्तार करते हुए नहर पार क्षेत्र को ग्रेटर फरीदाबाद का नाम देते हुए जनसुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

72 लाख परिवारों की पीपीपी आईडी बनाई गई है और पात्र लोगों को चिरायु हरियाणा, निरोगी हरियाणा सहित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता के साथ सरकार अंत्योदय की भावना से काम कर रही है।

'जी–20' शिखर सम्मेलन की तैयारियां हेतु झज्जर के प्रतापगढ़ फार्म का दौरा

(दिनांक 13.01.2023)

प्रभाव : मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में हो रहे जी–20 शिखर सम्मेलन की प्रदेश में होने वाली प्रस्तावित बैठकों के सफल आयोजन के लिए सरकार ने तैयारियां आरंभ कर दी हैं। इन बैठकों में पहुंचने वाले विदेशी मेहमानों को प्रदेश की समृद्ध कला एवं संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए भी विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने झज्जर के प्रतापगढ़ फार्म का दौरा किया। उन्होंने यहां हरियाणा के पारंपरिक जनजीवन पर आधारित खेल–कूद, कला संस्कृति, खान–पान, कृषि, बागवानी व पशुपालन से जुड़ी गतिविधियों का अवलोकन भी किया। इस मौके पर मुख्मयंत्री जी ने प्रदेशवासियों को लोहड़ी एवं मकर संक्रांति के पर्व की शुभकामनाएं भी दी। इसके उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जी–20 शिखर सम्मेलन की प्रदेश में होने वाली बैठकों के प्रबंधों को पुख्ता बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज प्रतापगढ़ फार्म का दौरा कर एक ही स्थान पर ग्रामीण जनजीवन के सामूहिक दर्शन से वे बेहद प्रभावित हुए हैं। इस फार्म के माध्यम से विलेज टूरिज्म को प्रोत्साहन मिला है। भिंडावास व सुलतानपुर पक्षी अभ्यारण्य रामसर साइट से जुड़ चुके है और एनसीआर में होने के कारण आने वाले समय में यहां पर पर्यटन को बढ़ावा अवश्य मिलेगा।

साप्ताहिक सूचना पत्र

लोहड़ी

(दिनांक 13.01.2023)

प्रभाव : मुख्यमंत्री जी ने शुक्रवार को हर्षोल्लास के साथ आमजन के बीच लोहड़ी का पावन त्योहार मनाया। करनाल के प्रेमनगर में स्थित कम्युनिटी सेंटर में आयोजित लोहड़ी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने शिरकत की और बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों को लोहड़ी की हार्दिक बधाई दी। उन्होंने प्रदेशवासियों की खुशहाली व तरक्की की प्रार्थना भी की।

इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि यह उनके लिए बड़े हर्ष का विषय है कि लोहड़ी के दिन वे करनाल शहर में मौजूद हैं और लोगों के बीच इस पावन पर्व को मना रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यह हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि यहां अलग–अलग त्योहार मनाए जाते हैं। लोहड़ी खुशियां बांटने का त्योहार है। उन्होंने कहा कि इस पावन त्योहार पर

वह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी के जीवन में सुख–समृद्धि आए। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल व अन्य अतिथियों ने अग्नि को तिल, गुड़ व मूंगफली अर्पित की। लोहड़ी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी ने आम जनता के साथ सीधे संवाद किया। इस दौरान बड़ी संख्या में आम लोगों, कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने एक–एक व्यक्ति से मिलकर लोहड़ी की बधाई ली और उनकी बातों को भी सुना।

साप्ताहिक सूचना पत्र

ग्राम सरंक्षकों से किया सीधा संवाद

(दिनांक 14.01.2023)

प्रभाव : मुख्यमंत्री जी ने 'ग्राम सरंक्षक संवाद कार्यक्रम' के तहत आज यहां ऑडियो–कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्राम–संरक्षकों से संवाद करते हुए उन्हें जमीनी स्तर पर गांवों में हो रहे कार्यों का मौके पर जाकर आंकलन कर सरकार को फीडबैक रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए, ताकि विकास कार्यों से जुड़े संबंधित विभागों को इसकी जानकारी दी जा सके। यदि कहीं कोई कमी होगी तो उसमें तुरंत सुधार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्राम संरक्षकों को गांवों को परिवार मानकर सेवा भाव से कार्य करना चाहिए।

लगभग 1.30 घंटे चले इस संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी 22 जिलों के श्रेणी– 1 के अधिकारी, जो ग्राम संरक्षक नामित किए गए हैं, से उनके द्वारा निरीक्षण किए गए कार्यों की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विकास का रास्ता गांव से होकर जाता है, जब गांवों का विकास होगा, तभी प्रदेश का

समुचित विकास सुनिश्चित होगा। इसलिए संरक्षकों को विशेष रूप से गांवों में हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करें। मुख्य रूप से पार्क एवं व्यायामशाला, आंगनवाड़ी केंद्रों, शिवधाम नवीनीकरण योजना के तहत शमशान घाट में चारदीवारी, पानी की व्यवस्थाा, शेड और पक्का रास्ता आदि कार्यों की समीक्षा कर रिपोर्ट ीजजचेरूध्ध्पदजतीतल.हवअ.पद पोर्टल पर अपलोड करें। इसके अलावा, ग्राम संरक्षक गांवों में 25 हजार से कम वार्षिक आय वाले परिवारों से भी संपर्क करें और अपनी रिपोर्ट भेजें, ताकि सरकार ऐसे परिवारों को मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष प्रयास कर सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से विशेष कैंप लगवाकर ऐसे परिवारों के सदस्यों को रोजगार मुहैया करवाएंगे, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके।

उन्होंने कहा कि वर्ष में कम से कम 6 बार ग्राम सभाओं की बैठकों का

आयोजन होना चाहिए। ग्राम संरक्षक सरपंचों के साथ समन्वय स्थामपित कर इन सभाओं का आयोजन कर ग्रामीणों को सरकार की अन्य योजनाओं से भी अवगत करवाएं व उन्हे जागरूक करें।

साप्ताहिक सूचना पत्र

हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 266 योग सहायकों को ऑनलाइन जॉब ऑफर

(दिनांक 14.01.2023)

प्रभाव : मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को अनूठे ढंग से मना रहा है, 21 जून, 2023 को पडने वाले अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इस बार हरियाणा का ग्रामीण अंचल भी पूरी तरह से योगमयी नजर आएगा। इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है। सर्वप्रथम मकर संक्रांति के दिन मुख्यमंत्री ने एक क्लिक के साथ हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 266 योग सहायकों को ऑनलाइन जॉब ऑफर भेजे। लगभग 340 योग सहायकों को पहले ही नियुक्त किया जा चुका है जो ग्रामीण अंचल में बनाए गए पार्क एवं व्यायामशालाओं में लोगों को योग के प्रति प्रेरित करेंगे। कबड्डी व कुश्ती जैसे पारंपरिक खेलों में देश व विदेश में पहचान बना चुका हरियाणा अब योग में भी चमकता नजर आएगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि क्लास–I स्तर के अधिकारियों को ग्राम संरक्षक के रूप में गांवों के पार्कों एवं व्यायाम शालाओं का निरीक्षण कर सीधे इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजने की जिम्मेदारी इन अधिकारियों को दी गई है । इस कड़ी में 3000 से अधिक अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ तीन चरण के संवाद में जुड़े हैं। मुख्यमंत्री ने इन अधिकारियों को कहा है कि अब गांवों के युवा क्लब, भूतपूर्व सैनिकों या प्रबुद्ध नागरिकों की एक समिति बनवाकर भी इन पार्क एवं व्यायामशालाओं का रखरखाव सुनिश्चित करें।